



पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ति4/ वि.व. 2024 परिणाम

निवेशक बैठक

मई 15, 2024

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रबंधन टीम:-

- सुश्री परमिंदर चोपड़ा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)-  
अतिरिक्त प्रभार
- श्री राजीव रंजन झा – निदेशक (परियोजना)
- श्री मनोज शर्मा – निदेशक (वाणिज्यिक)
- श्री अजय तिवारी – सरकारी नामित निदेशक
- श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक
- सुश्री उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक
- श्री प्रसन्न तंत्री, स्वतंत्र निदेशक

**समन्वयक:**

सुप्रभात देवियों और सज्जनों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से, हम आप सभी का इस इन्वेस्टर मीट में स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। पीएफसी हमेशा अपने निवेशकों से जुड़ने और निवेश समुदाय के साथ एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने का लक्ष्य रखती है। इसी उद्देश्य से, आज का कार्यक्रम वर्तमान और संभावित निवेशकों के साथ पीएफसी के वित्तीय कार्य निष्पादन और भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है।

अब, मैं पीएफसी के प्रबंधन का परिचय देना चाहूंगा: मंच पर, मेरे बाईं ओर हैं: श्री प्रसन्ना तंत्री, स्वतंत्र निदेशक, श्री भास्कर भट्टाचार्य, स्वतंत्र निदेशक, श्री अजय तिवारी, सरकार द्वारा नामित निदेशक, सुश्री परमिंदर चोपड़ा - सीएमडी, निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार, श्री राजीव रंजन झा- निदेशक (परियोजना), श्री मनोज शर्मा- निदेशक (वाणिज्यिक) और सुश्री उषा सजीव नायर, स्वतंत्र निदेशक

आज की वार्षिक निवेशक बैठक का कार्यक्रम दो भागों में होगा: सबसे पहले, पीएफसी के सीएमडी वित्त वर्ष 2024 के कार्य निष्पादन पर चर्चा करेंगी, उसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र होगा।

फिर, हम यूएसएआईडी द्वारा भारत के ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य पर एक प्रस्तुतिकरण देखेंगे। यूएसएआईडी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी है और इसने छह देशों - बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में सस्ती, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुँच में सुधार के लिए अपना दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा भागीदारी कार्यक्रम (SAREP) शुरू किया है। हाल ही में, पीएफसी ने अपनी ईएसजी गतिविधियों में सहायता के लिए यूएसएआईडी एसएआरईपी टीम के साथ भागीदारी की है।

अब मैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती परमिंदर चोपड़ा को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी।

**परमिंदर चोपड़ा :**

शुभ संध्या, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोविड काल के बाद यह हमारी पहली निवेशक बैठक है, और मुझे हमारे निवेशक समुदाय से अच्छी प्रतिक्रिया देखकर खुशी हुई। आज सुबह, मार्च 2024 को समाप्त होने वाले चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए पीएफसी के परिणाम घोषित किए गए हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फिर से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

में पीएफसी के समेकित कार्य निष्पादन से शुरुआत करूंगी। समूह स्तर पर, पीएफसी साल दर साल मजबूत कार्य निष्पादन कर रहा है। हम 10.40 लाख करोड़ के समेकित बैलेंस शीट आकार के साथ भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी समूह बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2024 के लिए, समेकित पीएटी 26,461 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष से 25% की वृद्धि है। समूह ऋण परिसंपत्ति बही में 16% की वृद्धि दर्ज की गई। परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले पर, हम अपने एनपीए स्तरों में कमी की प्रवृत्ति देखना जारी रखते हैं। वित्त वर्ष 24 के लिए समेकित शुद्ध एनपीए अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 1.03% की तुलना में 0.85% है।

अब पीएफसी स्टैंडअलोन कार्य निष्पादन की बात करें तो

सबसे पहले, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 14,367 करोड़ का सर्वकालिक उच्चतम वार्षिक लाभ अर्जित करके वर्ष का समापन उच्च स्तर पर किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 24% अधिक है। इसके साथ ही, पीएफसी अब भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली एनबीएफसी बन गई है। मुझे यह देखकर संतुष्टि हो रही है कि हमारा बॉटम लाइन साल दर साल बढ़ रहा है। यह मुख्य रूप से हमारे बेहतर होते मार्जिन के कारण है, जबकि प्रावधान, जोखिम प्रबंधन और शासन में विवेक सुनिश्चित करना है।

हमारे लगातार बढ़ते मुनाफे से हम अपने मूल्यवान निवेशकों और शेयरधारकों को हर साल जोखिम से अधिकतम लाभ दे पाते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बोर्ड ने प्रति शेयर ढाई रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जिसका भुगतान एजीएम की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 24 के लिए लाभांश 13 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर हो गया है। इस लाभांश के साथ इस वित्त वर्ष में पहले से दिए गए 1:4 के बोनस का भी लाभ मिलता है। इसलिए अगर मैं प्री बोनस लेवल पर बात करूं तो प्रति शेयर लाभांश 16 रुपये 88 पैसे प्रति शेयर होता।

अब प्रमुख वित्तीय अनुपातों की बात करें तो हम यह साझा कर रहे हैं कि हम 2.5% की सीमा में प्रसार को लक्षित कर रहे हैं। मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने वित्त वर्ष 2024 के लिए 3.46% के शुद्ध ब्याज मार्जिन के साथ 2.64% का प्रसार हासिल किया है। स्प्रेड मुख्य रूप से स्थिर लाभ और वित्त वर्ष 2024 में फंड की लागत में सुधार से प्रेरित है।

वित्त वर्ष 24 के लिए प्रतिफल 10.01% है। लागत पक्ष पर, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी कमी आई है और यह 7.37% पर है। पिछले साल से बाजार काफी अस्थिर रहा है, इसलिए हम फंड की लागत पर कड़ा नियंत्रण रख रहे हैं। हम एक सक्रिय देयता प्रबंधन रणनीति के माध्यम से अपनी लागतों को बनाए रख रहे हैं, जो इस पर केंद्रित है - जब भी अवसर उपलब्ध हो, उच्च लागत वाले ऋण को बदलना। फिर फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट ऋण का मिश्रण बनाए रखना।

और अंत में, घरेलू और विदेशी मुद्रा उधारी के बीच संतुलन बनाना।

पिछले वर्ष, हमने विविध मिश्रण बनाए रखने के अपने रणनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप लगभग 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे, हमारी जुटाई गई राशि का 18% विदेशी मुद्रा ऋण के माध्यम से था, जिसमें अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण का मिश्रण था।

विदेशी मुद्रा ऋण के बारे में बात करते हुए, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि जोखिम प्रबंधन के लिए हमारे पास एक बहुत ही सक्रिय ट्रेजरी डेस्क है। अभी, हमारे पोर्टफोलियो का 88% हिस्सा विनिमय दर के लिए सुरक्षित है, जबकि पिछले साल यह 66% था। 5 साल तक की शेष परिपक्वता वाले पोर्टफोलियो के लिए विनिमय दर जोखिम का 90% से अधिक हिस्सा सुरक्षित है। और अगर मैं 5 साल तक की शेष परिपक्वता की बात करूं, तो अमेरिकी डॉलर-मूल्यवान पोर्टफोलियो के लिए, विनिमय जोखिम का 100% कवर किया गया है। ये संख्याएँ हमें यह कहने का विश्वास दिलाती हैं कि हम भविष्य में व्यापक विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव की स्थिति में अपनी निचली रेखा को बनाए रख सकते हैं।

इसके अलावा, हमारा 25% का मजबूत पूंजी पर्याप्तता अनुपात और 79,000 करोड़ रुपये से अधिक का मजबूत नेटवर्थ वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और भविष्य की अनिश्चितताओं का प्रबंधन करने में सुविधा प्रदान करता है।

लचीलेपन के बारे में बात करते हुए, मैं हमारी परिसंपत्ति गुणवत्ता पर चर्चा करना चाहूंगी। एक साल से अधिक समय से, हमने कोई नया एनपीए नहीं जोड़ा है। हम एनपीए पोर्टफोलियो पर 74% प्रावधान बनाए रखना जारी रखते हैं, जो पिछले वर्ष के समान स्तर पर है। हमारे विवेकपूर्ण प्रावधान और समाधान के लिए सक्रिय प्रयासों के कारण, हमारे सकल एनपीए पिछले वर्ष के 1.07% से घटकर 0.85% हो गए हैं। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में, हमारी एनपीए बुक में लगभग 50% की कमी आई है। हमारा वर्तमान सकल एनपीए स्तर 3.34% है।

अभी हमारे पास कुल 16,000 करोड़ की NPA बुक है, जिसमें 21 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से लगभग 14,000 करोड़ की 13 परियोजनाओं का समाधान एनसीएलटी के माध्यम से किया जा रहा है, जिनमें से 2,600 करोड़ की 7 परियोजनाएँ परिसमापन के अधीन हैं। शेष 2,200 करोड़ की 8 परियोजनाएँ एनसीएलटी के बाहर हल की जा रही हैं। इन 21 संकटग्रस्त परियोजनाओं में से 2,900 करोड़ की बकाया राशि वाली 2 परियोजनाएँ, यानी कुल एनपीए बुक का 18% समाधान के उन्नत चरण में हैं।

सबसे पहले लैंको अमरकंटक परियोजना है, जिस पर 2,400 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह 1920 मेगावाट की ताप विद्युत उत्पादन परियोजना है। समाधान को मार्च 2024 में एनसीएलटी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है, और अभी भी मंजूरी का इंतजार है। विवेकपूर्ण अभ्यास के रूप में, हम इस परियोजना के लिए 76% प्रावधान बनाए रखना जारी रखते हैं। समाधान योजना के अनुसार, हमें 35% से अधिक मूलधन वसूली की उम्मीद है।

दूसरी परियोजना शिगा एनर्जी परियोजना है, जिस पर 522 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह 97 मेगावाट की चालू जल ऊर्जा परियोजना है। इसके लिए एनसीएलटी के बाहर समाधान की कोशिश की जा रही है। पुनर्गठन योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएफसी ने योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, और अन्य ऋणदाता अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में, हमारे पास परिसंपत्ति पर 31% प्रावधान है, और हमें इस परिसंपत्ति के लिए समाधान योजना से 100% मूलधन वसूली की उम्मीद है।

इन दो परिसंपत्तियों के समाधान के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा एनपीए 3% से नीचे आ जाएगा।

में अन्य दो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के विकास को साझा करना चाहेंगी जहां समाधान प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

इनमें से एक है केएसके महानदी परियोजना, जिस पर 3,300 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह 3,600 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना है। यह परियोजना एनसीएलटी के अधीन है। पिछले महीने, अभीरुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई थी, और इसमें सक्रिय भागीदारी देखी गई थी, जिसमें 26 अभीरुचि की अभिव्यक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। और हम जल्द ही एक आरएफपी जारी करेंगे। इस परियोजना के लिए, हम पहले से ही 55% प्रावधान बनाए हुए हैं।

एक अन्य परिसंपत्ति सिनार थर्मल पावर परियोजना है, जिस पर 3,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह 1350 मेगावाट का कोयला आधारित संयंत्र है। इस परियोजना को सितंबर 2022 में एनसीएलटी के तहत स्वीकार किया गया था, और उसी महीने समाधान कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। अब रोक हटा दी गई है, और 24 मार्च को अभीरुचि की अभिव्यक्ति प्रकाशित की गई है। 16 अभीरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। और इसमें भी, हम जल्द ही आरएफपी जारी करेंगे। हम इस परियोजना में 80% प्रावधान बनाए रख रहे हैं।

समग्र प्रावधान के फ्रंट पर, वर्ष के दौरान चरण 3 प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और हमने पिछले वर्ष के समान 74% प्रावधान को बनाए रखा है। हमारा मानना है कि ये प्रावधान स्तर पर्याप्त हैं।

विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, प्रबंधन ने ईसीएल ओवरले के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। तदनुसार, हमने वर्ष के दौरान लगभग 800 करोड़ रुपये की मानक परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान बनाया है, जो चरण एक और चरण दो

की परिसंपत्तियां हैं। वर्तमान में, हमारे पास मानक परिसंपत्तियों पर लगभग 0.85% का प्रावधान है।

अब मैं पीएफसी को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहूंगी। पहला है पीएफसी की ऋण पुस्तिका, और दूसरा है कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए आरबीआई के हाल ही में जारी किए गए मसौदा दिशानिर्देशों का प्रभाव।

ऋण पुस्तिका के मामले पर, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 24 में, हमने अपने वादे को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

पीएफसी ने ऋण परिसंपत्तियों में 14% की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है। यहां, मैं यह साझा करना चाहूंगी कि हमारी अक्षय ऊर्जा बुक ने साल दर साल 25% की वृद्धि हासिल की है। इसके साथ, अक्षय ऋण पोर्टफोलियो लगभग 60,000 करोड़ रुपये है। ऋण परिसंपत्ति वृद्धि वर्ष के दौरान 1,27,660 करोड़ रुपये के मजबूत संवितरण द्वारा संचालित थी।

ऋण पुस्तिका के बारे में बात करते हुए, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि आरईसी में 14,500 करोड़ रुपये के निवेश पर विचार करने के बाद पीएफसी की निवेश परिसंपत्ति पुस्तिका 4,95,000 के करीब है।

आरईसी में निवेश हमारी ऋण परिसंपत्तियों के समान है क्योंकि यह हमारे नियमित निवेश का हिस्सा नहीं है। यह उस पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अन्यथा ऋण देने के लिए लगाया जाता। आरईसी निवेश ने इस वर्ष लगभग 15% का रिटर्न दिया है। यदि हम आरईसी निवेश सहित अपनी आय पुस्तक पर कुल रिटर्न पर विचार करते हैं, तो हमारा लाभ 10.18 प्रतिशत है और स्प्रेड 2.81% है। समग्र आय के दृष्टिकोण से, पीएफसी की परिसंपत्ति पुस्तक मजबूत रिटर्न दे रही है। यह भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली एनबीएफसी के रूप में हमारी स्थिति से और अधिक परिलक्षित होता है।

अब हम भविष्य की ऋण वृद्धि रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ, मैं लचीलापन बनाने की हमारी रणनीति पर जोर देना चाहती हूँ। पीएफसी एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी है जो स्टैंडअलोन आधार पर 4.95 लाख करोड़ की संपत्ति बुक का प्रबंधन करती है। पीएफसी जैसी बड़ी कंपनी के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम आज जो वृद्धि हासिल करते हैं, वह कंपनी को आने वाले दशकों तक बनाए रखने और बढ़ने में सक्षम बनाती है।

अब, अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग वातावरण पिछले कुछ वर्षों में लगातार जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ब्याज दरें एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, बाज़ार में अस्थिरता बनी हुई है और भू-राजनीतिक वातावरण लगातार बदल रहा है। इन हालिया चुनौतियों ने किसी संगठन के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के महत्व को सामने ला दिया है। इसलिए, आज के माहौल की मांग है कि कंपनियों के पास स्थिर लाभ वृद्धि के साथ एक स्थिर वित्तीय आधार होना चाहिए, जो अनिश्चितताओं को संभालने के लिए लचीला हो।

इसे ध्यान में रखते हुए, पीएफसी में, हम "3R" के आदर्श वाक्य द्वारा निर्देशित होते हैं: यथार्थवादी, लचीला और मजबूत ऋण वृद्धि। हम अपनी ऋण पुस्तिका को इस तरह से विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यह वर्षों तक बनी रहे, एक स्थिर बॉटम लाइन प्रदान करे और मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखे। हमारा लक्ष्य मूल्य और मात्रा के बीच संतुलन बनाना है, जिससे हम साल दर साल लगातार वृद्धि हासिल कर सकें और एक मजबूत और अधिक लचीला पीएफसी बना सकें। इस दृष्टिकोण के साथ, हम अगले वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह की ऋण पुस्तिका वृद्धि की उम्मीद करते हैं। विकास के प्रमुख चालकों में ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में व्यवसाय शामिल होंगे, जैसे कि पारंपरिक सौर और पवन और ऊर्जा भंडारण समाधान के साथ-साथ वितरण क्षेत्र में ऋण देना, मुख्य रूप से आरबीपीएफ योजना के तहत।

इसके अलावा, जब तक अक्षय ऊर्जा की मांग और ऊर्जा स्थिरता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण जनसमूह तक नहीं पहुंच जाती। ऊर्जा सुरक्षा के लिए पारंपरिक उत्पादन के लिए धन की आवश्यकता होगी। यह पीएफसी के लिए एक और संभावित ऋण क्षेत्र होगा। अब तक, हमने स्थापित क्षमता का 50% समर्थन किया है और हमें उम्मीद है कि हम अपनी बाजार हिस्सेदारी को इसी सीमा में बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऋण भी हमारी ऋण परिसंपत्ति वृद्धि में वृद्धिशील रूप से योगदान देगा। कुल मिलाकर, अगले कुछ वर्षों में हमारी वृद्धि बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अवसरों के विविध मिश्रण से आएगी।

ऊर्जा परिवर्तन पर एक सिंहावलोकन देने के लिए, यूएसएआईडी के श्री मयंक आज शाम एक प्रस्तुति देंगे। हालाँकि, मैं वितरण क्षेत्र में हो रहे सुधारों पर संक्षेप में बात करना चाहूँगी, जो मूल्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

जैसा कि आप जानते ही होंगे, पीएफसी अपनी विकासात्मक भूमिका के तहत इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है और सरकारी सुधार योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। पीएफसी पिछले कई वर्षों से रेटिंग का काम कर रहा है।

हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों की 12वीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की गई है। यह डिस्कॉम के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। अगर हम 11वीं रेटिंग रिपोर्ट से परिणामों की तुलना करें तो इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वित्त वर्ष 23 में एटी एंड सी घाटा वित्त वर्ष 22 में 16.2% से घटकर 15.4% हो गया है, जो 12 से 15% के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब है। बिलिंग दक्षता वित्त वर्ष 22 में 86% से बढ़कर 87% हो गई है। विलंबित भुगतान अधिभार योजना के कार्यान्वयन के साथ, DISCOMS को GENCO और Transco को देय दिनों की संख्या वित्त वर्ष 23 में 166 दिनों से घटकर 126 दिन हो गई है। यहाँ, मैं यह साझा करना चाहूँगी कि LPS नियमों के कार्यान्वयन के बाद,

विरासत बकाया का 72% भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 24 के लिए 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समय पर टैरिफ आदेश जारी किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 23 में 20 और वित्त वर्ष 22 में 14 थे। इसलिए सुधार उपाय और लागू की गई वित्तपोषण योजनाओं के परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यह बिजली क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है।

आइए अब कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए आरबीआई परिपत्र के मसौदे पर आते हैं। हम समझते हैं कि इन विनियमों पर निवेशकों की मुख्य चिंताओं में से एक प्रावधान पर संभावित प्रभाव है। इस पहली बात पर, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के उद्देश्य से, पीएफसी अपेक्षित ऋण हानि की IND-AS पद्धति को लागू कर रहा है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एएस मानदंडों के अलावा आईसीएपी के तहत आवश्यक किसी भी वृद्धिशील प्रावधान को हानि आरक्षित के माध्यम से बनाया जाना चाहिए, न कि P&L के माध्यम से। इसलिए इन मसौदा दिशानिर्देशों के तहत किसी भी प्रावधान प्रभाव का कंपनी की लाभप्रदता पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी, वित्तीय संस्थान के बीच परिपत्रों की बारीकियों पर अभी भी चर्चा हो रही है।

इसलिए मध्यम से दीर्घ अवधि में प्रभाव का आकलन करने के लिए, हमें अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। बस एक विचार देने के लिए, यदि हम अपनी वर्तमान बकाया पुस्तक को देखें, तो कुल पुस्तक का लगभग 25% निर्माणाधीन है। अब हमारी प्रारंभिक समझ के आधार पर, मुख्य रूप से निर्माणाधीन चरण की परियोजनाओं के लिए प्रावधान की आवश्यकता है जहाँ डीसीसीओ विस्तार का विकल्प चुना गया है। निर्माणाधीन पोर्टफोलियो में, लगभग 45% पारंपरिक उत्पादन परियोजनाएँ हैं, जो आम तौर पर लंबी अवधि की होती हैं, और जहाँ डीसीसीओ को आमतौर पर बढ़ाया जाता है। शेष नवीकरणीय और संचरण और वितरण परियोजनाओं की ओर है, वे तुलनात्मक रूप से कम अवधि की होती हैं।

इसलिए यदि आरबीआई केवल उन मामलों पर प्रावधान लागू करने के लिए इस समझ पर स्पष्टीकरण देता है जहाँ डीसीसीओ विस्तार का विकल्प चुना गया है, तो संभावित प्रभावित पोर्टफोलियो बहुत कम होगा। यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्तमान में हम चरण एक और चरण दो परिसंपत्तियों पर लगभग 0.85% का औसत संयुक्त प्रावधान बनाए हुए हैं।

अब अगली चिंता यह है कि अतिरिक्त प्रावधान के लिए परियोजना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए पहला सवाल यह है कि हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे और क्या पूंजी में यह वृद्धि परियोजना ऋण लागत में वृद्धि करेगी।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे पास 15% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले 25% का मजबूत पूंजी पर्याप्तता स्तर है। टियर वन पूंजी 10% की आवश्यकता के मुकाबले 23% पर है।

ये संख्याएँ हमें भविष्य में ऋण वृद्धि के लिए पर्याप्त कमफर्ट देती हैं। पूंजी पर भविष्य के प्रभाव पर, स्थिति गतिशील है क्योंकि मसौदा परिपत्र के कार्यान्वयन पर अभी भी चर्चा की जा रही है। लेकिन आरबीआई वित्तीय संस्थानों के पूंजी स्तरों की सुरक्षा पर केंद्रित है और चिंता को समझने के लिए तैयार है। वित्तीय संस्थान के बीच परिपत्र पर चर्चा की जा रही है, और यदि कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आती है, तो उसे आरबीआई के समक्ष उठाया जाएगा।

यह कहने के बाद, अगर पूंजी जुटाने की कोई जरूरत पड़ती है, तो पीएफसी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सतत ऋण जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके लिए हमारे पास आरबीआई की सीमा के तहत पर्याप्त और पर्याप्त कुशन उपलब्ध है। पूंजी जुटाने की हमारी क्षमता को देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि कारोबार विकास को प्रभावित किए बिना सामान्य रूप से चलता रहेगा।

अब कोई भी अतिरिक्त पूंजी ऋण देने की लागत को प्रभावित करेगी, लेकिन यह सब भविष्य की स्पष्टता और आरबीआई से अंतिम मार्गदर्शन और ब्याज दर व्यवस्था कैसे काम करती है, इस पर निर्भर करेगा। स्थिति अभी भी विकसित हो रही है, और जब और अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी तो हम प्रभाव साझा करेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि पीएफसी भारत में ऊर्जा क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है, जिसमें ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य भी शामिल हैं। इस दिशा में, वित्त वर्ष 24 में, पीएफसी ने आईएफएससी गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपनी सहायक कंपनी पीएफसी इफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड की स्थापना की है।

हम आईएफएससी गिफ्ट सिटी में परिचालन स्थापित करने वाली पहली सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी हैं। यह सहायक कंपनी विद्युत क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करेगी। हमने पहले ही सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है। हम आईएफएससी सहायक कंपनी को भारत के विकास को वित्तपोषित करने के लिए एक आशाजनक मार्ग के रूप में देखते हैं।

अंत में, हम मानते हैं कि उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत बुनियादी बातों के संयोजन से पीएफसी भविष्य के विकास के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं।

#### **समन्वयक:**

धन्यवाद, मैडम। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लेंगे। जैसे ही आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, एक बोलांटियर माइक लेकर आपके पास आएगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना परिचय दें और कंपनी का नाम बताएं।

**श्रेया शिवानी :**

धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया है। मैं सीएलएसए से हूँ। मेरे पास 2 प्रश्न हैं। पहला आरबीआईविनियमन और वर्तमान ऋण पुस्तिका पर है। तो, मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि आपके DISCOM और अल्पावधि ऋणों में से, कितना प्रोजेक्ट फाइनेंस माना जाएगा? क्या आपके सभी DISCOM ऋणों को प्रोजेक्ट फाइनेंस माना जाएगा? मेरा मतलब है, हमारे LPS और हमारे ऋणों पर आदर्श रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर आपका क्या विचार और समझ है? और दूसरा, महोदया, थर्मल कैपेक्स पर है। तो हमारे पास, मीडिया लेखों और सहकर्मि टिप्पणियों के आधार पर जो हमने सुना है, वह लगभग 94 गीगावाट थर्मल कैपेक्स की योजना बना रहा है, जिसमें से 74 गैर NTPC होंगे। तो, आपका ऋण वृद्धि मार्गदर्शन 12% से 15% है, क्या इसमें आने वाले थर्मल कैपेक्स को शामिल किया गया है? इस पर आपका क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि थर्मल कैपेक्स वास्तव में कब शुरू होगा?

**परमिंदर चोपड़ा :**

डिस्कॉम ऋण के संबंध में, विशेष रूप से इन एलपीएस, एलआईएस और आरबीपीएफ के तहत, ये गैर-परियोजना ऋण हैं। इसलिए हमारी समझ के अनुसार, आरबीआई परिपत्र, हालिया मसौदा दिशानिर्देश उन पर लागू नहीं होंगे।

**श्रेया शिवानी :**

महोदया, यह आपके कुल डिस्कॉम का कितना हिस्सा होगा?

**परमिंदर चोपड़ा :**

मुझे लगता है कि DISCOM पोर्टफोलियो का लगभग 70% हिस्सा इन योजनाओं का होगा। उस हिस्से के लिए थर्मल जेनरेशन कैपेक्स में वृद्धि के बारे में आपके दूसरे प्रश्न पर। तो हम उसे वित्तपोषित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि आपने सही कहा कि इसका अधिकांश हिस्सा NTPC के अंतर्गत आ रहा है, और NTPC एक केंद्रीय क्षेत्र है, और वे PFC से उधार लेने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि राज्यों में कुछ आ रहा है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हम उसे वित्तपोषित करेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसी परियोजनाएँ आ रही हों जिन पर यह एक जारी संवितरण है। परियोजनाएँ स्वीकृत हो गई हैं, लेकिन क्षमताएँ अभी आनी बाकी हैं या परियोजना अभी चालू नहीं हुई है। इसलिए उस मोर्चे पर, हम अभी भी संवितरण करेंगे। लेकिन अगर नई योजनाएँ आ रही हैं, तो हम उसके अनुसार योजना बनाएंगे।

**श्रेया शिवानी :**

मैडम, पारंपरिक या थर्मल, जेनको बुक पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए, तो एक विश्लेषण से पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रकार की परियोजनाएं हैं जो हमारे सहकर्मी के लिए थर्मल, बुक में भी शामिल हैं। तो, क्या हम ऐसी परियोजनाओं में भाग नहीं लेते हैं या क्योंकि प्रवृत्ति यह है कि पीएफसी, थर्मल जेनको या पारंपरिक जेनको बुक या तो स्थिर रही है या घट रही है जबकि एक सहकर्मी के लिए, वह बुक बढ़ रही है? और विकास का मुख्य कारण इन ईएंडएम प्रकार के ऋणों में भागीदारी है। तो, क्या हम उनमें भाग नहीं ले रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं और इस पर हमारे क्या विचार हैं?

**परमिंदर चोपड़ा :**

देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं प्रतिस्पर्धियों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पीएफसी के लिए, हम जो जनरेशन पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं वह विशुद्ध रूप से उत्पादन पोर्टफोलियो है। ईएंडएम हिस्से को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

**श्रेया शिवानी :**

अतः ई एंड एम भाग में आप भाग नहीं लेते हैं या यह अन्य ऋण पुस्तिका में भी नहीं है।

**राजीव रंजन झा:**

नहीं, निश्चित रूप से, हम E&M के तहत भाग लेते हैं, लेकिन यह पुस्तक में नहीं दिखाई देता है क्योंकि यह उत्पादन की ओर नहीं ले जाता है। कुछ योजनाओं में इलेक्ट्रोमैकेनिकल घटक हैं जहाँ हम भाग लेते हैं।

**परमिंदर चोपड़ा :**

तो यह अन्य ऋण पुस्तिका में दिखाई दे रहा है।

**श्रेया शिवानी :**

समझ गई। बहुत उपयोगी है। धन्यवाद मैडम।

**आंद्रे पुरुषोत्तम :**

नमस्ते। मेरा नाम आंद्रे पुरुषोत्तम है। हम एक पारिवारिक कार्यालय का हिस्सा हैं, मैं और मेरी पत्नी। और हम आपकी कंपनी में शेयरधारक हैं। सबसे पहले, मैडम, क्या मैं आपको और आपकी टीम को बेहतरीन कार्य निष्पादन के लिए बधाई दे सकता हूँ। यह सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई।

मेरे पास दो सवाल थे। पहला सवाल लागत के मामले पर था और क्या आप इसे ऋण लेने की लागत और परिचालन लागत दोनों में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ तक परिचालन लागत का सवाल है, क्या कोई ऐसा लीवर है जिससे आपको

वरिष्ठ और महंगे कर्मियों की सेवानिवृत्ति या लागत में कटौती के मामले में और अधिक दक्षता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जो प्रौद्योगिकी की सहायता से हो सकती है? यह सवाल का एक हिस्सा है। और जहाँ तक ऋण लेने की लागत पर विचार किया जाता है, आपने उच्च लागत वाले ऋण की सेवानिवृत्ति का उल्लेख किया। तो क्या आपको उस क्षेत्र में अगले एक या दो वर्षों में कोई महत्वपूर्ण अवसर दिखाई देता है? और, इसलिए, क्या हम अगले 1 या 2 वर्षों में लागत में प्रतिशत या अन्यथा कोई महत्वपूर्ण कमी देख सकते हैं? यह मेरा पहला सवाल है।

#### **परमिंदर चोपड़ा :**

परिचालन लागत पर, आप जिस लागत का उल्लेख कर रहे हैं, उसे पीएफसी के समग्र राजस्व पर विचार करते हुए, वह हिस्सा नगण्य है। मैं जो अधिकतम राशि साझा कर सकती हूँ वह CSR व्यय 2% है, जिसे हमें वहन करना है। अन्यथा, हमारी लागत बहुत कम है क्योंकि जहाँ तक जनशक्ति का सवाल है, हम एक बहुत ही कमज़ोर संगठन हैं। इसलिए यह हमारे लिए प्रमुख परिचालन लागतों में योगदान नहीं देता है। दूसरी तरफ आपका अगला सवाल क्या था?

#### **आंद्रे पुरुषोत्तम :**

ऋण लेने की लागत, उच्च लागत वाले ऋण और किसी भी अन्य उपाय पर जो आपकी लागत को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं और इस प्रकार आपके मार्जिन में सुधार कर सकते हैं।

#### **परमिंदर चोपड़ा :**

ऋण में 2 तरह के लोन शामिल हैं। एक बॉण्ड है जिसे हम बाजार से ऋण लेते हैं और यह निश्चित दर पर होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई पूर्व भुगतान विकल्प नहीं होता है। दूसरा हिस्सा बैंकों से लिए गए लोन हैं, जहां दरें फ्लोटिंग होती हैं, लेकिन साथ ही पूर्व भुगतान विकल्प भी होता है, और आम तौर पर, इनकी कीमत बॉण्ड की कीमतों से थोड़ी अधिक होती है क्योंकि इनमें पूर्व भुगतान की सुविधा होती है। इसलिए हम जिस महंगे लोन या उच्च लागत वाले लोन की वापसी की बात कर रहे थे, वह मुख्य रूप से टर्म लोन था जिसे हमने बैंकों से उधार लिया था। या तो बैंकों ने मौजूदा लोन में पीएफसी को ऋण देने के लिए ब्याज दर कम करने का फैसला किया है, या फिर पूर्व भुगतान के बाद, उन्होंने बाद में पीएफसी को कम दर पर लोन दिया है।

#### **आंद्रे पुरुषोत्तम :**

और एक और सवाल जो मैंने पूछा, मैम, वह जोखिमों के बारे में था। आपने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, क्या अगले एक या दो सालों में कोई महत्वपूर्ण जोखिम है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है?

**परमिंदर चोपड़ा :**

देखिए, एक, क्रेडिट लागत पर, मुझे लगता है कि प्रावधान के मामले पर, हमारे पास चरण एक, चरण दो, साथ ही चरण 3 परिसंपत्ति दोनों पर पर्याप्त कुशन है। इसलिए हम उस मामले पर कोई अतिरिक्त बड़ा जोखिम नहीं देख रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे-जैसे हमारा नियामक अनुपालन बढ़ाएगा, तो यह उन जोखिमों में से एक हो सकता है जिन्हें हम इन मसौदा दिशानिर्देशों की तरह देख सकते हैं। इसलिए हर कोई, सभी निवेशक चिंतित हैं कि इसका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो यह एक जोखिम है जो नियामक के दृष्टिकोण से हमेशा खुला रहता है। और दूसरा यह हो सकता है कि विनिमय दर में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव हो रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारी समझ है, ये दो बड़े जोखिम हैं।

**आंद्रे पुरुषोत्तम :**

बहुत बहुत धन्यवाद महोदया

**श्वेता:**

नमस्ते मैडम। एलारा कैपिटल से श्वेता। मैडम, मेरे पास कुछ सवाल हैं। तो एक, आपके सहकर्मी ने सबसे बड़े लेखा पर प्रावधान रिवर्सल किया है जो लैंको अमरकंटक संपर्क है। तो क्या ऐसा है कि हमारे एलजीडी/पीडी, धारणाएँ अलग-अलग हैं और इसीलिए, तो क्यों, आप जानते हैं, जैसे, समान लेखा होने के बावजूद, प्रावधान रिवर्सल पर लेखा अवधि अलग-अलग है और इसलिए, क्या हम इसे ति1 में आने की उम्मीद कर रहे हैं?

**परमिंदर चोपड़ा:**

देखिए, मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप अपने निकटतम साथियों के संदर्भ में प्रश्न न पूछें। आप पूछ सकते हैं कि पीएफसी द्वारा रिवर्सल क्यों नहीं किया गया। यह प्रश्न पूछने का बेहतर तरीका होगा।

**श्वेता:**

जी

**परमिंदर चोपड़ा:**

इसलिए हमारी नीति के अनुसार, जब हमें अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी और जब समाधान योजना लागू हो जाएगी। इसलिए हम उस चरण में प्रावधान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए एनसीएलटी की मंजूरी अभी भी लंबित है। हम एनसीएलटी की मंजूरी मिलने और समाधान योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं,

जिसके बाद हम रिवर्सल करेंगे। और जाहिर है, जब हम रिवर्सल करेंगे, तो हम दोनों एक ही मंच पर होंगे।

**श्वेता:**

ठीक है और महोदया, बस एक संबंधित प्रश्न। तो आपने अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया है कि, हमने चरण एक और दो पर अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये का मानक परिसंपत्ति प्रावधान किया है। तो यह नए मसौदा मानदंडों के अनुरूप है या, क्या यह उससे अलग है? और यदि ऐसा है, तो, आपको अतिरिक्त प्रावधान करने के लिए क्या प्रेरित किया?

**परमिंदर चोपड़ा:**

देखिए, यह प्रबंधन ओवरले, जिसकी हम बात कर रहे थे, हमने ति3 तक पहले ही कर लिया है। इसलिए यह इस विशेष तिमाही में नहीं है कि हमने कोई प्रबंधन ओवरले किया है। इसलिए मसौदा दिशानिर्देश उससे बहुत बाद में आए हैं। इसलिए यह किया गया। हमारे पास कुछ रिवर्सल थे। लेकिन एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, हमने सोचा कि हमें एक मजबूत परिसंपत्ति बही और किसी भी भविष्य की अनिश्चितताओं का ख्याल रखने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना चाहिए। इसलिए उस लेखा पर, हमने उस विकल्प का प्रयोग किया है, और आप देख रहे हैं कि समग्र आधार पर, हमारे पास केवल 134 या 124 करोड़ रुपये का रिवर्सल है।

**श्वेता:**

इसके अलावा, पुनः इससे संबंधित, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश में थोड़ी वृद्धि हो रही है और क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं?

**परमिंदर चोपड़ा:**

देखिए, एक बार प्रबंधन द्वारा ओवरले का प्रयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सभी स्टेज वन परिसंपत्तियों पर समग्र कुशन बनाने के लिए। हमने प्रावधान को पोर्टफोलियो स्तर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से न्यूनतम 0.4% तक बढ़ा दिया है। इसलिए प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है।

**श्वेता:**

महोदया, एक आखिरी सवाल और मैं विकास पर जोर दूंगी। इसलिए अगर मेरी समझ सही है तो मुझे सही करें। इसलिए हम 12 से 15 प्रतिशत ऋण वृद्धि का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बिजली क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला अवसरों के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए भले ही आपने पिछले प्रश्न में उत्तर दिया हो कि थर्मल पक्ष में, मोटे तौर पर, एनटीपीसी 94 गीगावाट, स्थापना क्षमता से ऊपर उठने वाला है, जो अपेक्षित है। लेकिन, चूंकि हम बैटरी और भंडारण जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के शुरुआती चरणों में हैं, इसलिए थर्मल कोयले के साथ फिर से पर्याप्त अवसर हैं।

बिंदु संख्या 1. बिंदु संख्या 2 नवीकरणीय पक्ष पर, हम 313, अतिरिक्त वृद्धिशील आवश्यकता की भी उम्मीद कर रहे हैं, और आज हम 187 के आसपास बहुत कम हैं। और, अगर मैं इसे वार्षिक आधार पर लेती हूँ, तो हम केवल 12 गीगावाट हैं और मैं रूफटॉप सौर वित्तपोषण अवसर के बारे में बात भी नहीं कर रही हूँ। डिस्कॉम पक्ष पर, वितरण पूंजीगत व्यय अभी भी जारी है और हमने अभी भी बही के इंफ्रा पक्ष का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है। तो हम, पूरे बिजली मूल्य श्रृंखला में इस तरह के वित्तपोषण अवसर और क्षमता के बावजूद, हमारे विकास अनुमानों में थोड़ी रूढ़िवादिता का कारण क्या है? और बस, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग, तो जब आपने स्पष्ट रूप से समझाया कि नए RBI ड्राफ्ट, मानदंड, इस तथ्य को देखते हुए कि हम पूंजी पर्याप्तता पर उच्च हैं, यह हमारी पूंजी को उस सीमा तक भी नहीं खपा सकता है। तो, यदि आप इन दोनों पर बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, हम विकास लक्ष्यों पर कहां से आ रहे हैं, आप जानते हैं, जहां आपके पास 15% से अधिक विकास क्षमता है? धन्यवाद।

#### **परमिंदर चोपड़ा:**

देखिए, हम हमेशा से इस बारे में बात करते रहे हैं कि हम 12 से 15% के बीच की दर से बढ़ेंगे। इसलिए आपको यह समझना होगा कि हमारा आधार बढ़ रहा है जिस पर हम विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए आधार 4,57,000 से बढ़कर 4,81,000 हो गया है। इसलिए तदनुसार, हम यथार्थवादी लक्ष्य देना चाहते हैं जिसे हम प्राप्त कर सकें और हम इसे लंबे समय तक बनाए रख सकें। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, हम उसे निधि दे रहे हैं। हमें पीएफसी के भविष्य को बनाए रखने के लिए अपनी बही को बढ़ाना है। इसलिए यही वह आदर्श वाक्य है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए, यह एक रूढ़िवादी संख्या लग सकती है, लेकिन वास्तव में, हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, हम दे रहे हैं। यदि अधिक संभावना है, तो हम इसे करने के लिए हमेशा तैयार हैं, यदि हमें अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं मिलती हैं। इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं। इस पर, मसौदा दिशा-निर्देशों के प्रभाव के बारे में आपका दूसरा प्रश्न, मुझे लगता है कि इन दिशा-निर्देशों पर बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। फिर भी, हर कोई जितना अधिक पढ़ेगा, उतना ही अधिक भ्रम पैदा करेगा। इसलिए आपको किस पोर्टफोलियो पर आवेदन करना है, आपको कैसे आवेदन करना है, इसे कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए उन सभी चीजों पर बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। हम आरबीआई को अपनी टिप्पणियाँ देंगे और देखेंगे कि आरबीआई जब भी अंतिम दिशा-निर्देशों के लिए आएगा, तो क्या निष्कर्ष निकालेगा। इसलिए मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ।

**रमेश भोजवानी:**

मैडम, रमेश भोजवानी मेहता से। आपके आने से पहले हमने आपकी AV प्रस्तुति देखी। यह लगातार चल रही थी। और यह देखकर बहुत खुशी हुई कि हमने जो हासिल किया है, लगभग 230 से 240 गीगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता। हम अगले 5 या 7 वर्षों में आगे बढ़ते हुए दोगुना होने की संभावना रखते हैं। और आप 86 से 2024 तक बिल्कुल उसी बिंदु पर स्थित हैं। यह परिसंपत्ति आधार और वित्त पोषण अगले 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, यही मैं देख रहा हूँ। बस इस पर आपके विचार। और दूसरी, एक छोटी सी बात, T&D घाटा 15.43% तक कम हो गया है, यह देखकर बहुत खुशी हुई। स्मार्ट मीटर लगाने की मदद से क्या हम इसे एक अंक के नुकसान तक नहीं घटा सकते हैं ताकि हम बिजली तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसे खो रहे हैं? असल में, मेरा मानना है कि हम बिजली चोरी के कारण इसे खो रहे हैं। हम इसे T & D नुकसान के रूप में अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन यह बिजली चोरी के अलावा और कुछ नहीं है। और स्मार्ट मीटर की मदद से हम इस बिजली के खतरे को रोक सकते हैं। और यह T & D नुकसान एक अंक तक कम हो सकता है। हो सकता है कि लंबी दूरी के ट्रांसमिशन की वजह से नुकसान हो। दोनों पर आपके विचार।

**परमिंदर चोपड़ा:**

इसलिए क्षमता को दोगुना करने के बारे में, मैं यह साझा करना चाहूँगी कि पीएफ़सी ने देश में कुल स्थापित क्षमता का 50% समर्थन किया है। और अगर मैं नवीकरणीय क्षमता की बात करूँ, तो हमने स्थापित क्षमता का 25% समर्थन किया है। और हमें उम्मीद है कि देश की बढ़ी हुई क्षमता में हमारा हिस्सा जारी रहेगा। तो यह एक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि T&D घाटे में पर्याप्त कमी आई है। और कुछ राज्यों में, यह देश के लिए औसत है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी, कुछ राज्यों में, हम पहले से ही एकल अंक में आने वाले T&D घाटे का अनुभव कर रहे हैं।

**रमेश भोजवानी:**

बहुत बढ़िया

**परमिंदर चोपड़ा:**

इसलिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके लिए यह विशेष औसत विकृत है। इसलिए हम सोचेंगे कि एक बार जब वे राज्य भी प्रदर्शन करेंगे, तो कुल मिलाकर देश के स्तर पर हम एकल अंक में उपलब्धि हासिल कर लेंगे।

**रमेश भोजवानी:**

और, मेरे मन में एक विचार आया कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में जिसका आपने उल्लेख किया है, हमें इसमें तेजी लाने की जरूरत है और जलविद्युत पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है। जब भी पूर्वोत्तर में भारी बारिश होती है, तो हमारे यहां बहुत सारे झरने होते हैं। वह पानी विनाश का कारण बनता है। बाढ़ और अतिप्रवाह के माध्यम से और, आप जानते हैं, हमने जो भी अन्य बुनियादी ढाँचा बनाया है वह नष्ट हो जाता है। यदि हम भारत के जलमार्गों के साथ चैनलाइज़ कर सकते हैं, तो न केवल हम विनाश या विनाश देख सकते हैं, बल्कि हम चार दक्षिणी राज्यों में पानी भी पहुँचा सकते हैं क्योंकि हर गर्मियों में, एक रिपोर्ट है कि लोग 20 रुपये में एक बाल्टी पानी खरीदते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर ऐसी चीज है जिसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, यह एक परिसंपत्ति है।

**परमिंदर चोपड़ा:**

मैं चाहूंगी कि हमारे सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री अजय तिवारी जवाब दें।

**रमेश भोजवानी:**

जी

**अजय तिवारी:**

यह प्रश्न वास्तव में पीएफसी से नहीं बल्कि सरकार से पूछा गया है।

**रमेश भोजवानी:**

जी

**अजय तिवारी:**

इसलिए, आज की तारीख में, हमारे पास देश में लगभग 47 गीगावाट की स्थापित क्षमता वाली जलविद्युत है, जिसमें पीएसपी की कुछ परियोजनाएँ भी शामिल हैं। 47 गीगावाट से, अब हम प्रयास कर रहे हैं, बीच में एक खामोशी थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा सस्ती दरों पर आ रही थी। इसलिए हाइड्रो सेक्टर में बहुत खामोशी थी। लेकिन अब सरकार हाइड्रो पावर पर अतिरिक्त जोर दे रही है क्योंकि यह बहुत स्थिर है, यह आपकी पीक पावर आवश्यकता को पूरा करती है जो ग्रिड में आपकी आरई इंटरमिटेंसी को भी संतुलित करती है।

**रमेश भोजवानी:**

जी

**अजय तिवारी:**

तो यह बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बिजली है। इसलिए हमने इस पर बहुत जोर दिया है। और पिछले साल ही अगस्त के महीने में अगर आपने अखबारों में सुना होगा या पढ़ा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में ही भारत सरकार ने 13 गीगावाट की 13 परियोजनाओं के लिए 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हाँ, एक दिन में 13 गीगावाट के करीब 13 प्रोजेक्ट।

**रमेश भोजवानी:**

और एक राज्य में?

**अजय तिवारी:**

एक राज्य में

जैसा कि आपने कहा, अरुणाचल में बहुत अधिक जलविद्युत क्षमता है।

**रमेश भोजवानी:**

हां

**अजय तिवारी:**

पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 60% बिजली क्षमता है। इसलिए हम अन्य राज्यों के अलावा इसका भी दोहन कर रहे हैं। हमने एक नई योजना शुरू की है, जिसे बहुत जल्द मंजूरी मिलने वाली है, जो राज्य सरकारों को इक्विटी के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता की तरह होगी ताकि वे प्रत्येक हाइड्रो प्रोजेक्ट में 24 प्रतिशत तक की भागीदारी कर सकें। ताकि वे भी परियोजना में पूरी तरह से शामिल हो सकें और बाद में उन्हें राजस्व भी मिले। इसी तरह, अन्य राज्यों में भी कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की तरह, बहुत सारी परियोजनाएँ आ रही हैं। और, आप जल्द ही देश में फिर से हाइड्रोबॉल की वृद्धि देखेंगे। लेकिन ऊर्जा मिश्रण में प्रतिशत के संदर्भ में, यह 2047 तक भी लगभग 12% के आसपास रहने वाला है। क्योंकि सौर और पवन आरई आ रहे हैं। हमने देश में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। तो, बस इतना ही।

**रमेश भोजवानी:**

और, महोदय, एक बात जो आपने ठीक से नहीं कही, वह यह है कि जब हमारे पास उत्तर-पूर्व में अतिरिक्त पानी होता है, तो यह हमारे द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे या जीवन को नुकसान पहुंचाता है और नष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम उसी पानी को भारत के उत्तर, उत्तर-पूर्व से लेकर पूरे दक्षिण तक जलमार्ग या नदी मार्ग बनाकर प्रवाहित कर सकें, तो हम पूरे देश के लिए पानी की इस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।

### **अजय तिवारी:**

इसलिए अगर परियोजनाएं हाइड्रो के अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं तो इसका ध्यान रखा जाएगा। इसलिए हमारा विचार मूल रूप से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए जाना है, जो सिंचाई में भी योगदान देगा, बाढ़ को कम करेगा। साथ ही, आपके वनस्पतियों और जीवों की जैव विविधता को बहाल करेगा। पूर्वोत्तर में हम सभी जानते हैं कि कई अन्य, गैर-रणनीतिक महत्व हैं। तो ये वो चीजें हैं और, जो नुकसान आप कह रहे हैं वह डाउनस्ट्रीम के कारण होता है।

अगर ये बड़ी परियोजनाएं ऊपरी पहुंच, मध्य और निचले इलाकों में आती हैं, जैसा कि हमने योजना बनाई है, तो यह सब ध्यान में रखा जा सकता है। और मूल रूप से और भी योजनाएं आएंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर ऊंचे क्षेत्रों में और भी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

### **रमेश भोजवानी:**

आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं

### **समन्वय:**

हम एक और प्रश्न लेंगे, और हम पीछे से भी एक प्रश्न लेंगे क्योंकि हमारे पास एक और प्रस्तुति है।

हां। आगे बताएं।

हमारे लिए दूसरी सबसे बड़ी, संकटग्रस्त परिसंपत्ति थर्मल पावर परियोजना है। तो आपने अभी बात की, एक प्रक्रिया है जो अदालती मामलों के बाद फिर से शुरू हुई। तो क्या अगले एक साल में परियोजना पूरी तरह से शुरू हो जाएगी? क्योंकि यह लगभग पूरी होने वाली थी जब सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रावधान इस सिन्नर पावर प्रोजेक्ट में भी सबसे बड़ा है।

### **राजीव रंजन झा:**

वह सिन्नर बिजली परियोजना लगभग 1350 मेगावाट की है, 270 मेगावाट की 5 इकाइयाँ। इसलिए इस परियोजना को एनसीएलटी में ले जाया गया है। और आप जानते ही होंगे। इसलिए सीओसी की ओर से आरपी को हमारा पहला निर्देश है कि इकाइयों को चालू किया जाए, कम से कम 2 इकाइयों को चालू किया जाए। इसलिए, क्योंकि कोयला परिवहन में एक सीमा है। इसलिए, क्योंकि कोयला परिवहन में एक सीमा है। कोयला साइडिंग रेलवे साइडिंग वास्तव में उपलब्ध नहीं है। इसलिए केवल सड़क मार्ग से ही कोयले का परिवहन किया जा सकता है। इसलिए पहला निर्देश 2 इकाइयों को चालू करने का है। इसलिए आरपी उस दिशा में काम कर रहा है। यही मैं

करना चाहता हूँ। और समाधान प्रक्रिया चल रही है।

कितना प्रावधान किया गया है?

**परमिंदर चोपड़ा:**

80%.

**समन्वयक:**

हम अपनी अगली प्रस्तुति पर जाने से पहले एक अंतिम प्रश्न लेंगे।

**मनोज चंदानी:**

बहुत ही स्पष्ट बात कही और आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। श्री तिवारी के लिए कुछ विचार। कल वित्त मंत्री ने जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल होने के कारण \$20,000,000 के प्रवाह के बारे में बात की। पीएफसी इसे कैसे हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने रुपये के फायदे के बारे में भी बात की। तो जाहिर है, हेजिंग की लागत भी कम हो गई है, और यह एक बढ़िया अवसर है। और श्री तिवारी और सीईओ, अगर आप इसका उल्लेख कर सकते हैं, तो हम इसके लिए कैसे तैयार हैं। बिंदु संख्या 2. फिर से, श्री तिवारी, क्या विचार हैं। हम सबसे बड़ी एनवीएफसी हैं। आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन जाहिर तौर पर उच्च लाभ और बहुत कम मूल्य पर बुक करने के साथ बहुत कम मूल्यांकित है। यदि समेकन होता है तो इसमें और सुधार हो सकता है। आज, 2 कंपनियाँ हैं और बहुत ज़्यादा क्रॉस होलिंग है। तो श्री तिवारी, आप सबसे बड़े शेयरधारक यानी सरकार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं और यह सिर्फ 7, पीई या, आप जानते हैं, सिर्फ 5 पीई का पूर्वानुमान और सबसे बड़ा होने से मूल्यांकन को और बेहतर बना सकता है जो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। लेकिन आप कोविड के बाद आए हैं। आपने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम मनोज जैन चंदानी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**परमिंदर चोपड़ा:**

मुझे लगता है कि आपने 2 सवाल उठाए हैं। पहला जेपी मॉर्गन इंडेक्स पर था। इसलिए हमने घोषणा के बाद पहले ही मूल्यांकन में वृद्धि देखी है, और हमें उम्मीद है कि यह परिणाम के बाद और समग्र बिजली क्षेत्र परिदृश्य को देखते हुए और भी बढ़ेगा। रुपये पर, हाँ, मैं सहमत हूँ कि सरकार ने घोषणा की है, लेकिन बाजार अभी भी विकसित होना बाकी है। इसलिए यह केवल इतना ही नहीं है कि हम रुपये में बाहरी बाजार से धन जुटाना चाहते हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि दूसरे पक्ष के लिए हमें उधार देने वाला व्यक्ति या संस्था, यह कैसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव बनाती है।

क्योंकि हम पूरी तरह से बैलेंस शीट, पीएफसी की बैलेंस शीट की ताकत के आधार पर ही पैसे जुटा रहे हैं। इस संबंध में हमें भारत सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला है। इसलिए यह दोनों पक्षों के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव होना चाहिए। अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं श्री तिवारी की ओर से जवाब देना चाहूंगी। समेकन के मोर्चे पर, हां, होल्ड कंपनी डिस्काउंट का मुद्दा है और आप देख रहे हैं कि स्टॉक की कीमत कम है।

आप जानते हैं, अधिग्रहण के समय, अधिग्रहण के लिए इरादा, तार्किक निष्कर्ष दोनों कंपनियों का विलय था। लेकिन किसी तरह सरकार की कई अन्य प्राथमिकताओं के कारण, चाहे वह कोविड हो, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो या अन्य कारक। किसी तरह इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया गया और हम अपने, सम्मान या बहुसंख्यक शेयरधारकों का इंतजार कर रहे हैं, जब भी आने वाले समय में इस पर विचार प्रक्रिया की जाएगी, तो हमें इस संबंध में दिशा मिलेगी। आप जानते हैं कि सौदे के साथ कुछ मुद्दे भी हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले बहुत अधिक विचार प्रक्रिया की आवश्यकता है।

#### **समन्वयक:**

धन्यवाद। इस प्रश्नोत्तर में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं यूएसएआईडी एसएआरईपी से श्री मयंक भारद्वाज को भारत के ऊर्जा संक्रमण परिदृश्य पर एक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री मयंक भारद्वाज ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें वित्तीय मूल्यांकन और लेनदेन सलाह में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वर्तमान में वे एसएआरईपी के स्वच्छ ऊर्जा निवेश जुटाने के कार्यक्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं।

#### **मयंक भारद्वाज**

धन्यवाद। सबसे पहले, मैं पीएफसी को एसएआरईपी को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, आप जानते हैं, भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए इस सम्मोहक मामले को प्रस्तुत करने के लिए। मैं मुख्य रूप से विकास की कहानी को कवर करूंगा। पिछले कुछ वर्षों में बिजली क्षेत्र कैसे विकसित हुआ है।

विकास के लिए भविष्य के चालक क्या हैं? सरकार ने पहले ही कुछ लक्ष्य तय कर लिए हैं, नीतियों की घोषणा कर दी है। और, निवेश की संभावनाओं के बारे में कुछ आकलन किया है। तो इस तरह भारत में बिजली क्षेत्र का विकास हुआ है। अगर आप देखें, तो पिछले 20 वर्षों में स्थापित क्षमता में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति खपत में लगभग 2.4 गुना वृद्धि हुई है।

और, इसी तरह, हमने ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों में भी वृद्धि देखी है। तो पिछले 20 सालों में, यही कहानी है। और

यह बहुत, बहुत दिलचस्प हो जाता है, जैसे, मुझे लगता है, यहाँ से अगले 10 सालों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है। अब, अगर मैं कुछ कारकों, कुछ विकास कारकों को देखता हूँ, अब, अगर मैं कुछ विकास कारकों को देखता हूँ जो इसके लिए मौजूद हैं, तो उनमें से एक नीति है। सरकारी नीतियों ने निवेश के लिए यह अनुकूल माहौल बनाया है। आप देख सकते हैं कि भारत अभी भी प्रति व्यक्ति खपत में लगभग 1.2 पर है। वहाँ बहुत संभावना है। हम अभी भी विश्व औसत का लगभग 50% हैं। यह दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, फिर से, कुल बिजली खपत में लगभग 7% की CAGR डालने की उम्मीद है।

जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान क्षमता 442 गीगावाट है, जिसके अगले 6 से 7 वर्षों में 900 गीगावाट हो जाने की उम्मीद है। COP 21 लक्ष्य, जो निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले था, पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। तो, फिर से, एक अच्छा बाजार, विकास चालक सब कुछ ठीक है। सरकार ने पहले ही लक्ष्य की घोषणा कर दी है। तो यह एक ऐसा प्रयास है जो आया है, एक स्वैच्छिक प्रयास जो आया है, 2070 तक शुद्ध शून्य। दूसरा, जैसा कि सर ने 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता, गैर जीवाश्म क्षमता का भी उल्लेख किया है। सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन क्षमता में 45% की कमी। हम पहले ही गैर जीवाश्म में 200 गीगावाट क्षमता तक पहुँच चुके हैं, या उसके करीब हैं, जो कि भारत की वर्तमान स्थापित क्षमता का लगभग 45% है। 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद में 33% की कमी पहले ही हासिल की जा चुकी है। इसलिए हम अच्छी तरह से स्थापित हैं। हम उस ऊर्जा संक्रमण को प्राप्त करने और संभवतः उस पर पहुँचने के अपने मार्ग पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऊर्जा संक्रमण वास्तविक है। यह हो रहा है। यह केवल इसे और आगे बढ़ाने का सवाल है, बस उस अतिरिक्त धक्का को लेने का।

ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इस वृद्धि को गति देंगे। अक्षय ऊर्जा, हम में से अधिकांश इसके बारे में जानते हैं। ईवी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-मोबिलिटी जो आएगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, आरई से जुड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम जो वहाँ है और जैसा कि हम इसे कहते हैं, ब्लॉक पर नया बच्चा, ग्रीन हाइड्रोजन, जो वहाँ है। अगर मैं आरई, अक्षय ऊर्जा को देखता हूँ, तो हम लगभग 24%, 15%, बड़ी मात्रा में वार्षिक सीएजीआर वृद्धि देख रहे हैं। सौर ऊर्जा में लगभग 3.5 गुना वृद्धि की आवश्यकता है, पवन ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि की आवश्यकता है, भंडारण खंड में 6 या 12 गुना वृद्धि की आवश्यकता है।

फिर से, जैसा कि आप जानते हैं, भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को प्राप्त करने या नवीकरणीय ऊर्जा को सिस्टम में एकीकृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी नीतियाँ, वे वहाँ रही हैं। सौर ऊर्जा के विनिर्माण के लिए पीएलआई, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाएँ, जो वहाँ हैं। कुसुम योजना और हाल ही में सूर्य योजना की

घोषणा की गई, विशेष रूप से रूफटॉप सोलर के लिए। इस क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

ऊर्जा भंडारण, वीजीएफ, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की घोषणा की गई है। यह वहां है। निविदाएं पहले ही जारी हो चुकी हैं। इसके अलावा, एक प्रोत्साहन भी है। बैटरी के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना चल रही है जो भी लागू है।

उन्नत सेल रसायन विज्ञान, जैसा कि हम इसे कहते हैं, बैटरी निर्माण, पहेली के टुकड़े वास्तव में ऊपर चढ़ रहे हैं। साथ ही, कुछ नीतियां जो अपेक्षित थीं, जैसे कि DISCOMS के लिए RPO दायित्व, उन्हें 2030 तक अधिसूचित किया गया है। और, राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण पवन नीति भी वास्तव में तस्वीर में आई। पवन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए इसे फिर से अधिसूचित किया गया है क्योंकि पवन, फिर से, स्थान विशिष्ट है। और, बहुत अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो यह एक है। यह पवन क्षेत्र को आगे बढ़ाने और पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। ऑफशोर एक और है जो आपको इस साल के अंत में, या शायद अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, आरई से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली, जैसा कि हम देखते हैं कि अंतरराज्यीय ऊर्जा शुल्क, प्रेषित शुल्क पर अंतरराज्यीय छूट पहले से ही लागू है, आरई के लिए और अब ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के लिए भी। ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सेस नियमों को भी अधिसूचित किया गया है, अनुबंधित क्षमता 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट घंटा कर दी गई है। कहानी कुछ ऐसी ही है। अगले 7 से 8 वर्षों में 337 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इसका अधिकांश हिस्सा, 50 प्रतिशत सौर क्षेत्र में है।

और इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए लगभग 29 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जो कि मौजूद है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ई मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार ने पहले ही EV 30 को 30 पर लाने का लक्ष्य घोषित कर दिया है। इसलिए 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का 30% हिस्सा होना चाहिए। हमने इस क्षेत्र में वृद्धि देखी है। इसलिए 2022 की तुलना में 2023 में बिक्री में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभी, हमारे पास लगभग 16,000- 16,500 की सीमा में चार्जिंग स्टेशन हैं। और 2030 तक लगभग 80 गुना वृद्धि की आवश्यकता है। इसलिए 1,300,000 चार्जिंग स्टेशनों के आंकड़े तक पहुँचना है। फिर से, एक बहुत ही आशाजनक अवसर।

इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट पर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम के अनुसार, इसमें अभी 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश है, जिसमें लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लगाई जानी हैं। भारत में लगभग 23 लाख बसें हैं। तो आप इलेक्ट्रिक बस

सेगमेंट के लिए बाजार की संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं। भारत सरकार, अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर, राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा भुगतान में देरी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए भुगतान सुरक्षा स्थापित करने की योजना बना रही है। यह, फिर से, निवेशक जोखिम को कम करेगा, अधिक परियोजनाओं को अधिक बैंक योग्य बनाएगा, और बैंकों और वित्तपोषण संस्थानों को उन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रेरित करेगा।

एफएएमई, योजना एक और दो, फिर से, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन खरीदने के लिए चार्जिंग इंफ्रा-स्टेशन स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई थी। कुल मिलाकर, अगले 6 से 7 वर्षों में 192 बिलियन का निवेश अवसर है। चार्जिंग इंफ्रा में लगभग 3 बिलियन डॉलर और वाहन उत्पादन स्थान में लगभग 177 बिलियन डॉलर आने की उम्मीद है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस का बहुत बड़ा हिस्सा या अधिकांश हिस्सा शामिल होगा।

ग्रीन हाइड्रोजन, फिर से, बड़ा अवसर है। अगले 8 वर्षों में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता है। सरकार पहले ही एक राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आई है, जिसे हम SIGHT कार्यक्रम के तहत लगभग 3 बिलियन डॉलर की राशि दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने अगले 6 से 7 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर आकर्षित करने के लिए अनुदान और सब्सिडी की व्यवस्था की है। 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन घरेलू क्षमता की आवश्यकता है। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण और हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास, हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं को पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन और लगभग 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष लगभग 1500 मेगावाट प्रोत्साहन पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उत्पादन परियोजनाओं को पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। मुख्य रूप से, हाइड्रोजन, क्षेत्र, उपयोग के मामले रासायनिक विनिर्माण, औद्योगिक उपयोग, उर्वरक, पेट्रोलियम और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्रों में हैं। तो यह वही है जिसके बारे में हम 656 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कर रहे हैं।

फिर से, 8 साल। तो आप उस निवेश की मात्रा की कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे एक आकर्षक निवेश, अवसर कह रहा था। कुछ ऐसा जिसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें लोगों को भारत की ऊर्जा परिवर्तन कहानी का हिस्सा बनने के लिए भाग लेना चाहिए। फिर से, इसका अधिकांश हिस्सा, नवीकरणीय ऊर्जा में जाने की उम्मीद है, लगभग 50%, लगभग 336 बिलियन डॉलर, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, 190 बिलियन डॉलर।

अब मैंने सभी अच्छी चीजों के बारे में बात कर ली है। चुनौती क्या है? तो, कुछ चुनौतियाँ जो उभर रही हैं, वे हैं कि हम हर साल 10 गीगावाट, 12 गीगावाट, 15 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता वृद्धि हासिल करने में सक्षम हैं। और

हम ऐसा करने में बहुत सहज हैं। सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में इसे सालाना 40 गीगावाट या 45 गीगावाट तक बढ़ा सकते हैं? अगर आप पिछले 2 वर्षों को देखें, तो 2022 में, वित्त वर्ष 23 में, हम लगभग 15 गीगावाट, 15 से 16 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता हासिल करने में सक्षम थे। पिछले साल, वित्त वर्ष 24 में, हम 20 गीगावाट तक पहुँचने में सक्षम थे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम इसे 40, 45 तक बढ़ा सकते हैं और 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं या नहीं? जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार होता है, जैसे-जैसे ऊर्जा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, भंडारण का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो, फिर से, सवाल यह है कि भंडारण कैसे, कहाँ आ सकता है, और क्या अवसर हैं और कैसे आगे बढ़ें और सरकारी नीतियाँ वास्तव में ज़मीन पर कैसे लागू होती हैं। यह एक क्षेत्र है।

इसलिए, फिर से, पर्याप्त भंडारण क्षमता का विकास अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रवेश के लिए बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंतिम भाग, उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए कम लागत वाले फंड। फिर से, ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने, अपनाने में तेजी लाने, उन्हें पारंपरिक, आप जानते हैं, बर्फ वाहनों या पारंपरिक हाइड्रोजन, उत्पादन, प्रक्रियाओं के संबंध में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो, यह फिर से एक चुनौती बनी हुई है। वास्तव में, आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, आप जानते हैं, उन 2030 लक्ष्यों तक पहुँचना।

यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, एक प्रमुख पैरामीटर जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बदलाव क्यों? जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, और मैंने उस लेख को एक साथ कवर किया है कि पहले से ही एक सक्षम नीति वातावरण, महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, सरकार द्वारा एनडीसी की घोषणा की गई है। यह एक मजबूत घरेलू मांग है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता है, जो वहाँ है। समर्थन बुनियादी ढाँचा पहले से ही मौजूद है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे आरई से जुड़े ट्रांसमिशन जिनका मैंने उल्लेख किया है, पहले से ही मौजूद हैं ताकि अधिक से अधिक आरई आ सकें। तो ये कुछ प्रमुख कारक हैं, कुछ प्रमुख आप जानते हैं, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन कहानी क्यों है, और क्यों, वास्तव में इसमें निवेश करना चाहिए।

तो फिर पीएफसी कहाँ है?

और मुझे लगता है, हमने आज इस पर चर्चा की है। इसलिए पीएफसी हमेशा सबसे आगे रहा है और वास्तव में एक तरह से भारत की ऊर्जा परिवर्तन की कहानी में योगदान दे रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। 30 साल से अधिक, 3 दशकों का अनुभव, बिजली क्षेत्र में और अब इन्फ्रा स्पेस में भी विविधीकरण। लंबी अवधि के ऋण, जो 10 साल 15 साल के हैं, वास्तव में परिसंपत्ति-देयता बेमेल की समग्र अवधारणा के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी इसके बारे में जानते हैं। अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा ऋणदाता, यह भारत की लगभग

25% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का समर्थन करता है। और अंत में, इसने नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को मदद की है या उधार दिया है। इसने ई-मोबिलिटी और ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों को उधार दिया है। और अब यह अच्छी स्थिति में है या वास्तव में बहुत बढ़िया स्थिति में है, इन सभी को एक साथ रखने और इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण या भारत की ऊर्जा संक्रमण कहानी को आगे बढ़ाने या आगे बढ़ाने के लिए। बस इतना ही। धन्यवाद। और, यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। इस बार कहानी का नकारात्मक पक्ष क्या है?

प्रश्न: मेरे पास दो प्रश्न थे। पहला ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में है, ग्रीन हाइड्रोजन की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में आज हम कहां हैं और यदि अभी नहीं हैं, तो इसे नीचे आने में कितना समय लगेगा?

हां

क्या आपने मेरा प्रश्न सुना?

**मयंक भारद्वाज**

हाँ। हाँ। मैंने आपका सवाल सुना। तो, अभी, ग्रीन हाइड्रोजन, हम कहीं 4 से 5 डॉलर प्रति किलोग्राम के क्षेत्र में हैं, जो कि, फिर से, आप जानते हैं, जब आपको इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम से कम 2 से कम होना चाहिए। तो, आप जानते हैं, मैंने नीतियों के बारे में जो उल्लेख किया है, सरकार जो प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, उनसे इसे नीचे लाने की उम्मीद है। यदि आप अमेरिका को देखें, तो मुद्रास्फीति अधिनियम जो आया, लक्ष्य अगले 6 से 7 वर्षों में इसे 1 डॉलर से नीचे ले जाना है। तो यही अमेरिका का लक्ष्य है। भारत के लिए ऐसा कोई लक्ष्य या कोई समयसीमा नहीं है, लेकिन, अगले 3 से 4 वर्षों में क्योंकि ऐसा होने की उम्मीद है, आप जानते हैं, मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ।

यह यहाँ 2 से 3 डॉलर के स्तर तक कम हो सकता है। लेकिन यह 3 से 4 साल की अवधि में होगा। हाँ।

प्रश्न: आपने निर्यात प्रतिस्पर्धा का भी महत्वपूर्ण उल्लेख किया। ठीक है।

क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि भारत की क्षमताओं के संदर्भ में यह निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कहां से आती है और, हम इसे किस तरह देखते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि गंदी ऊर्जा के आयात में काफी बाधाएं होंगी। ठीक है?

## मयंक भारद्वाज

सही है। तो, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, मैं जानता हूँ, अगर मैं मुख्य रूप से ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के टुकड़ों को देखूँ, तो 2 या 3 कारक हैं। एक कारक जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है भूमि। ठीक है। अगर आप जापान और कोरिया को देखें, तो फिर से, भूमि एक बड़ा मुद्दा है। तो यह एक ऐसा हिस्सा है जहाँ यह आता है, दूसरा है अक्षय ऊर्जा शुल्क। ठीक है। तो भारत के टैरिफ, अक्षय ऊर्जा शुल्क अभी दुनिया में सबसे कम में से एक हैं, जो वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का एक प्रमुख घटक है। यह लागत का लगभग 40 से 45 प्रतिशत है। और तीसरा है, आप जानते हैं, श्रम लागत, जो वहाँ है, जिस पर हम बहुत सी चीज़ों पर ज़ोर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कुछ शायद तीन कारक हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कारक होंगे।

## अजय तिवारी :

मैं आपको इस बारे में, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में थोड़ा-बहुत बता सकता हूँ। हम जापान, सिंगापुर, जर्मनी और इसी तरह के अन्य देशों, यहाँ तक कि कोरिया को भी ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने का लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक समस्या है, जैसा कि उन्होंने अभी बताया, और, हमें वहाँ लाभ है। और ये देश ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत उत्सुक हैं, जिसके लिए वे इससे उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को भी साझा करने की संभावना रखते हैं। कुछ कार्बन क्रेडिट, वे अपने एनडीसी पर समायोजित करेंगे। और इसका एक हिस्सा, हम इसे अपने एनडीसी, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पर डालेंगे। इसलिए इन तीन देशों के बीच इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं।

हम वास्तव में इस पर काम कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और, बहुत जल्द हम देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट भी प्रतिस्पर्धात्मकता के कारकों में से एक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य कारकों के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया है। इसलिए ये वे प्रमुख बाजार हैं जिन पर हम वास्तव में नज़र रख रहे हैं।

## मयंक भारद्वाज

आपका कोई प्रश्न था?

सवाल: हाँ। यह एक बेहतरीन, शानदार बात है। सभी सकारात्मक बातें हैं। तो नकारात्मक पक्ष के बारे में आपका क्या विचार है?

## मयंक भारद्वाज

मैं इसका उत्तर पीएफसी की ओर से नहीं दूंगा। मैं आपको केवल अपना दृष्टिकोण बता सकता हूँ कि, एक तरह से नकारात्मक पक्ष यह है कि, नवीकरणीय ऊर्जा में रुकावट सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो कि मौजूद है और यदि आप पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं बना पाते हैं, तो यह कुछ हद तक एक चुनौती होगी। यह एक है, दूसरा हिस्सा स्पष्ट रूप से भारत का विकास कारक है। है न? अब यदि भारत का विकास कारक आपकी क्षमता वृद्धि या अन्य हिस्सों से आगे निकल रहा है, तो आपको इसे उस दृष्टिकोण से देखना होगा। तीसरा है ई-मोबिलिटी। है न? अब जब आप अपने सामान्य आइस से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी मांग होने वाली है, आप जानते

हैं, जो उत्पन्न होती है। अब हम इसे कैसे पूरा करेंगे और क्या हम तैयार हैं? तो बस कुछ शीर्ष चीजें, आप जानते हैं, जो सामने आती हैं, जो इस कहानी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, शायद, अगर, यह मेरे, विशेषज्ञ के, आप जानते हैं, दृष्टिकोण से है। बाकी अगर मैडम इस तरह की किसी चीज को जोड़ना चाहती हैं।

**अजय तिवारी :**

मैं उनकी बातों में कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। आज के समय में स्टोरेज सबसे बड़ी चुनौती है। और आप जो पूछ रहे हैं वह नकारात्मक पक्ष है। यह नकारात्मक पक्ष नहीं बल्कि एक चुनौती है जिसका हम सामना करेंगे। अमेरिका के साथ मिलकर इंडो यूएस टास्कफोर्स का गठन किया गया है जो इस बैटरी स्टोरेज की केमिस्ट्री को देखेगा।

चाहे वह सबसे बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज के लिए हो या स्कूटी और 4 व्हीलर के लिए मोबिलिटी के लिए। तो यह बैटरी, जो वास्तव में लिथियम का उपयोग करती है, जो एक दुर्लभ पृथ्वी सामग्री या महत्वपूर्ण खनिज है, यह हमारे लिए एक चुनौती है। इसलिए हम वैकल्पिक रसायन विज्ञान, सोडियम आधारित और अन्य प्रकार के बैटरी स्टोरेज की भी खोज कर रहे हैं, जिसके लिए भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

और यह एक बहुत ही अनोखी तरह की ऊर्जा भंडारण टास्क फोर्स है, ईएसटीएफ, जिसे हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान बनाया गया था, पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। तो यह बहुत उच्च स्तर पर तय किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह टास्क फोर्स पहले से ही उद्योग में काम कर रही है। यह भारतीय उद्योग में निहित है, सरकार के पास नहीं। इसलिए यह रातों-रात काम कर रहा है और हम उन समाधानों के साथ आने वाले हैं। और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह चुनौती भी होगी। और, यूएसएआईडी भी पूरे काम की कहानी का हिस्सा है कि जिस तरह से हम स्टोरेज पार्ट, बैटरी पार्ट पर काम कर रहे हैं, मूल रूप से।

प्रश्न: आपका क्या कहना है?

**परमिंदर चोपड़ा:**

मुझे लगता है कि एक वित्तीय संस्थान के रूप में हम इन प्रौद्योगिकियों को व्यवहार्य बनाने के लिए तकनीकी सुधार पर बहुत काम कर रहे हैं। इसलिए हम पहले से ही वहां हैं। और जैसा कि मुझे लगता है कि पहले भी हमारे निदेशक परियोजना ने कहा था कि हम इन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत में हम सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक बार जब ये पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाते हैं, तो हम इन सभी अवसरों को वित्तपोषित करने के लिए तैयार हैं।

बहुत बढ़िया। धन्यवाद। शुभकामनाएं।

**अजय तिवारी:**

उस स्टार्ट अप के बारे में बताइए, जो भारत में स्टोरेज आधारित तकनीकों पर पहले से ही काम कर रहा है। आईआईटी

बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और यह ऊर्जा भंडारण टास्क फोर्स, उद्योग, वे आईआईटी रुड़की परिसर और आईआईटी बॉम्बे में स्टार्ट अप से इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने वास्तव में इस तरह काम किया है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना रहे हैं और भारत बैटरियों के वैकल्पिक रसायन विज्ञान में रास्ता दिखाएगा। जरूर, आपका धन्यवाद।

**समन्वयक:**

धन्यवाद महोदय।

मुझे लगता है कि वहाँ वास्तव में बहुत सक्रिय भागीदारी थी, और मुझे यकीन है कि पीछे बैठे कुछ लोग सवाल पूछने से वंचित रह गए क्योंकि हम केवल आगे बैठे लोगों को ही देख रहे थे। देवियों और सज्जनों, हम इस अवसर पर आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे साथ यहाँ आए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाई टी के लिए हमारे साथ जुड़ें, और एक प्यारी शाम बिताएँ। अपना ख्याल रखें।